

**CUSTOMS, EXCISE & SERVICE TAX APPELLATE TRIBUNAL
ALLAHABAD**

REGIONAL BENCH - COURT NO.I

Customs Appeal No.70643 of 2021

(Arising out of Order-in-Appeal No.205-CUS/APPL/LKO/2021 dated 25.08.2021 passed by Commissioner (Appeals) Customs, GST & Central Excise, Lucknow)

Shri Saffikur Rahaman,

.....Appellant

(R/o Room No.70 Bhitni Part, Post-Dohariya
Distt.-Gorakhpur U.P.)

VERSUS

Commissioner of Customs, GST &

Central Excise, Lucknow

....Respondent

(Lucknow)

APPEARANCE:

Shri Anuj Agrawal, Advocate for the Appellant

Shri Santosh Kumar, Authorized Representative for the Respondent

CORAM: HON'BLE MR. SANJIV SRIVASTAVA, MEMBER (TECHNICAL)

FINAL ORDER NO.- 70279/2024

DATE OF HEARING : 28 May, 2024

DATE OF DECISION : 28 May, 2024

SANJIV SRIVASTAVA:

This appeal is directed against Order-in-Appeal No.205-CUS/APPL/LKO/2021 dated 25.08.2021 passed by Commissioner (Appeals) Customs, GST & Central Excise, Lucknow. By the impugned order learned Commissioner (Appeals) has upheld the Order-in-Original No.52/ADC/2020-21 dated 27.08.2020 passed by Commissioner (Preventive) Customs, Lucknow as under:-

आदेश

"39.1 मैं, श्री सफ़िकुर रहमान, उम्र 22 वर्ष, पुत्र श्री अब्दुल रहमान, निवासी रूम नंबर-70, भिटनी पार्ट, पोस्ट- दोहरिया, गोरखपुर, उ०प्र०- 273015, भारतीय पासपोर्ट सं. R- 7783604 के पास से अभिग्रहित (Seized) 933.000 ग्राम विदेशी सोना मूल्य रु०31,16,220/- (रु० इकतीस लाख सोलह हजार दो सौ बीस मात्र) को सीमा शुल्क अधिनियम,

1962 की धारा 111 (d), 111(l) एवं 111 (m) के प्रावधानों के अंतर्गत पूर्ण रूप से अधिहरण करने का आदेश देता हूँ।

39.2 मैं, श्री सफ़िकुर रहमान, उम्र 22 वर्ष, पुत्र श्री अब्दुल रहमान, निवासी रूम नंबर-70, भिटनी पार्ट, पोस्ट दोहरिया, गोरखपुर, उ०प्र०-273015, के पास से जब्त 933.000 ग्राम विदेशी सोना को रखने, ढोने व छिपाने में प्रयुक्त जब्त हथौड़ी एवं एक बैग, जिसका कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 119 के अंतर्गत पूर्ण रूप से अधिहरण (Absolute Confiscation) का आदेश देता हूँ।

39.3 मैं श्री सफ़िकुर रहमान, उम्र 22 वर्ष, पुत्र श्री अब्दुल रहमान, निवासी रूम नंबर-70, भिटनी पार्ट, पोस्ट- दोहरिया, गोरखपुर, उ०प्र०-273015, पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की उपरोक्त वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 112 (b) के अंतर्गत रुपये 10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र) का जुर्माना आरोपित करता हूँ।

39.4 मैं 'जिस किसी से सम्बंधित है' पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 112 के अन्तर्गत दण्ड लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता हूँ।"

2.1 The Appellant was intercepted from Lucknow Airport alongwith 933.000 grams of gold valued at Rs.31,16,220/-. After completion of investigation show cause notice dated 15.09.2019 was issued asking from the Appellant to show cause:-

"(1) (क) श्री सफ़िकुर रहमान, उम्र 22 वर्ष पुत्र श्री अब्दुल रहमान, निवासी- रूम नंबर-70, भिटनी पार्ट, पोस्ट-दोहरिया, गोरखपुर, उ०प्र०-273015, के पास से अभिग्रहित (Seized) 933.000 ग्राम विदेशी सोना मूल्य रु०31,16,220/- मात्र (रुपये इकतीस लाख सोलह हजार दो सौ बीस मात्र), जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन के द्वारा विदेश से भारत में अवैध रूप से आयात किया जा रहा था, को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 111 के प्रावधानों के अंतर्गत पूर्ण रूप से अधिग्रहित (absolute confiscation) कर लिया जाये।

(ख) उपरोक्त बरामद / जब्त विदेशी सोना 933.000 ग्राम को रखने, ढोने व छिपाने में प्रयुक्त हथौड़ी एवं एक बैग, जिसका कोई वाणिज्यिक

मूल्य नहीं है, को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 119 के अंतर्गत अधिग्नहित (confiscation) कर लिया जाये।

2. श्री सफ़िकुर रहमान उम्र 22 वर्ष, पुत्र श्री अब्दुल रहमान, निवासी-रूम नंबर 70, भिटनी पार्ट, पोस्ट-दोहरिया, गोरखपुर, उ०प्र०-273015, एवं जिस किसी से सम्बन्धित है पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की उपरोक्त वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 112 के अंतर्गत जुर्माना आरोपित किया जाये।"

2.2 Show cause notice was adjudicated against the Appellant as per the Order-in-Original referred above. Aggrieved Appellant filed the appeal before the learned Commissioner (Appeals) which has been dismissed as per the impugned order.

3.1 I have heard Shri Anuj Agrawal learned Advocate appearing on behalf of the Appellant and Shri Santosh Kumar learned Authorized Representative for the Revenue.

3.2 Learned Counsel for the Appellant submits that,-

- the Order-in-Original was passed without taking note of the fact that a copy of notice was never served upon the Appellant. Accordingly, he was not in a position to make compliance.
- No effective hearing also took place in the matter before the Original Authority.
- Appellant had filed the appeal before the learned Commissioner (Appeals) stating this ground as evident from the grounds of appeal in the appeal filed before the learned Commissioner (Appeals) at Serial No.8 as under:-
- Impugned order has not recorded any findings on this ground stated in the appeal. Therefore the impugned order is a non speaking order.
- the order has been passed in violation of principles of Natural Justice, without any opportunity being made available to the Appellant for making effective defence before the Original Authority.

➤In this appeal filed before the tribunal this fact has been stated in part No.6 of statement of fact and point No.D in the grounds of appeal.

3.3 Learned Authorized Representative reiterated the findings of the impugned order.

4.1 I have considered the impugned order along with the submissions made in the appeal and during the course of arguments.

4.2 In Order-in-Original No.52/ADC/2020-21 dated 27.08.2020 following has been recorded:-

"पार्टी का पक्ष:

17. उक्त कारण बताओ नोटिस के प्रत्युत्तर में जापी की ओर से कोई भी लिखित प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

व्यक्तिगत सुनवाई का रिकार्ड:

18. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए श्री सपिफकुर रहमान पुत्र श्री अब्दुल रहमान अपने बचाव में सभी साक्ष्यों एवं प्रमाण के साथ व्यक्तिगत सुनवाई हेतु क्रममाः दिनांक 25.06.2020, 03.07.2020 एवं 27.08.2020 को अधिनिर्णयन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिये पत्र प्रेषित किया गया परंतु इनमें से किन्हीं भी तिथियों पर न तो श्री सपिफकुर रहमान पुत्र श्री अब्दुल रहमान और न ही इनका कोई अधिकृत प्रतिनिधि अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित हुआ।

18.1 शापीगण अधिनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष 03 विभिन्न तिथियों पर अवसर प्रदान किए जाने के बाद भी व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुये। यह स्पष्ट रूप से मामले को सुस्त गति से लम्बित करने का मामला प्रतीत होता है। मेरे पास मामले से सम्बंधित तथ्यों, साक्ष्यों के आधार पर इसकी विवेचना और निर्णय करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पूर्ण और स्पष्ट ढंग से अनुसरण किया गया है।

18.2 मेरी इस धारणा को सहायक आयुक्त वाणिज्य कर विभाग बनाम शुक्ला एंड ब्रदर्स [2010 (254) ई.एल.टी.6) एस.सी.]] मामले में मा उच्चतम न्यायालय के निर्णय से समर्थन मिलता है जिसमें मा. न्यायालय ने यह कहा है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के दो अवयव होते हैं, यथा (1) प्राधिकारियों की कार्रवाई से प्रतिकूलतः प्रभावी होने वाले व्यक्ति को

कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए और (2) सुनवाई का अवसर। मा. न्यायालय का यह भी माना है कि किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार इनमें से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में आदेश दूषित हो जाता है।

18.3 इसके अतिरिक्त उमानाथ पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [2009 (237) ई.एल.टी. 241 (एस.सी.)] मामले में मा. उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के दो नियम हैं। प्रथम नियम है "hemojudget in causasua" अर्थात् "अपने ही मामले में कोई व्यक्ति निर्णायक नहीं बन सकता।" और प्राकृतिक न्याय का दूसरा नियम है "audi alteram partem" अर्थात् किसी भी व्यक्ति को सुने जाने के अधिकार से वंचित न रखा जाए।" मा. न्यायालय का यह भी मानना है कि नोटिस इस सिद्धांत का प्रथम अवयव है, नोटिस सटीक और स्पष्ट होनी चाहिए और आवश्यक है कि पक्षकार के विरुद्ध प्रतिकूल आदेश जारी करने से पहले उसको नोटिस जारी की जानी चाहिए। दूसरा अवयव यह है कि प्रदान किया गया समय इतना पर्याप्त हो कि पक्षकार अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सके।

18.4 इस केस में दोनों अवयवों को संतुष्टिपरक ढंग से निष्पादित किया गया है। जैसा कि पहले चर्चा की जा चुकी है कि जापियों को समुचित कारण बताओ नोटिस पहले ही जारी की जा चुकी है और इसकी प्राप्ति के सम्बंध में भी कोई विवाद नहीं है तथा जापियों को उनके मामले में बचाव के लिए सुनवाई के तर्कपूर्ण अवसर प्रदान किए गए हैं। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह सिद्ध हो जाता है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का व्यापक और ठोस रूप से अनुपालन किया गया है। अतः इस उपरिलिखित तथ्यों के आलोक में मैं इस मामले के न्याय - निर्णयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाता हूँ।"

4.3 The order of the Original Authority has been passed without service of the notice on the Appellant and without recording any fact with regard to the service. The order has been passed in contravention of the principles of natural justice. It is also informed that all the three days of hearing during the period which was fixed 25.06.2020, 03.07.2020 & 27.08.2020 when the entire country was struggling with Covid-19. Just because three days were assigned during that period for personal hearing this could not be held to be a grant of opportunity for personal

hearing to comply with the principles of natural justice specifically taking into this effect of Covid-19. Hon'ble Apex Court has in **Suo Motu Writ Petition (C) No.3 of 2020** vide order dated 10th January 2022 directed as follows:

"5. Taking into consideration the arguments advanced by learned counsel and the impact of the surge of the virus on public health and adversities faced by litigants in the prevailing conditions, we deem it appropriate to dispose of the M.A. No. 21 of 2022 with the following directions:

- I. The order dated 23.03.2020 is restored and in continuation of the subsequent orders dated 08.03.2021, 27.04.2021 and 23.09.2021, it is directed that the period from 15.03.2020 till 28.02.2022 shall stand excluded for the purposes of limitation as may be prescribed under any general or special laws in respect of all judicial or quasi-judicial proceedings.*
- II. Consequently, the balance period of limitation remaining as on 03.10.2021, if any, shall become available with effect from 01.03.2022.*
- III. In cases where the limitation would have expired during the period between 15.03.2020 till 28.02.2022, notwithstanding the actual balance period of limitation remaining, all persons shall have a limitation period of 90 days from 01.03.2022. In the event the actual balance period of limitation remaining, with effect from 01.03.2022 is greater than 90 days, that longer period shall apply.*
- IV. It is further clarified that the period from 15.03.2020 till 28.02.2022 shall also stand excluded in computing the periods prescribed under Sections 23 (4) and 29A of the Arbitration and Conciliation Act, 1996, Section 12A of the Commercial Courts Act, 2015 and provisos (b) and (c) of Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881 and any other laws, which prescribe period(s) of limitation for instituting proceedings, outer limits (within which the court or tribunal can condone delay) and termination of proceedings."*

4.4 Since the Original Authority has passed the order without compliance with the principles of natural justice and without ensuring the service of show cause notice on the Appellant which as submitted by the counsel for the Appellant has not been served even till date. Undisputedly Appellant has taken ground before the First Appellate authority as is evident by point No.8 in

the grounds of appeal filed by appellant before Commissioner (Appeal) reproduced below:

"8. That the no show causes notice was sent to the appellant by Customs. Therefore, appellant could not send to the reply of show cause notice."

Commissioner (Appeals) has not recorded any findings in the impugned order.

4.5 I do not find any merits in the impugned order and am inclined to remand this matter back to the Original Authority for *de novo* consideration.

5.1 Appeal allowed. Matter remanded to the Original Authority for *de novo* consideration.

5.2 Original Authority should within fifteen days receipt of this order ensure that show cause notice is duly served upon the Appellant and thereafter within ninety days re-adjudicate this matter after duly complying with the principles of natural justice.

5.3 The amounts deposited as pre-deposit for hearing of this appeal shall stand deposited with the concerned Adjudicating Authority till the disposal of the matter in remand proceedings by him. No refund claim shall be made by the Appellant for this amount during this period.

5.4 Appellant should also fully cooperate in the matter with adjudicating authority with regards to the service of notice and adjudication process by not seeking any adjournment whenever matter is listed.

(Dictated and pronounced in open court)

(SANJIV SRIVASTAVA)
MEMBER (TECHNICAL)

LKS